UPSC Daily Current Affairs 09 AUG 2021

माउंट मेरापी: इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में माउंट मेरापी जो इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, में जावा के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाके में विस्फोट हो गया।

माउंट मेरापी के बारे में जानकारी

- यह एक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है जो केंद्रीय जावा के प्रांत और योग्यकर्ता, इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र के बीच में सीमा पर स्थित है।
- यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और 1548 से नियमित तौर पर इसमें विस्फोट होते हैं।
- इंडोनेशिया भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधि से ग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि यह प्रशांत के 'अग्नि वलय' पर स्थित है। यह एक घोड़े की नाल के आकार की महासागर के चारों ओर भूकंपीय भ्रंश रेखाओं की एक श्रृंखला है।

संबंधित सूचना

- हाल में, **इंडोनेशियाई भूगर्भीय एजेंसी** ने रिपोर्ट दी है कि **जनवरी 2021 में माउंट सेमेरू पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था।**

माउंट सेमेरू के बारे में जानकारी

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

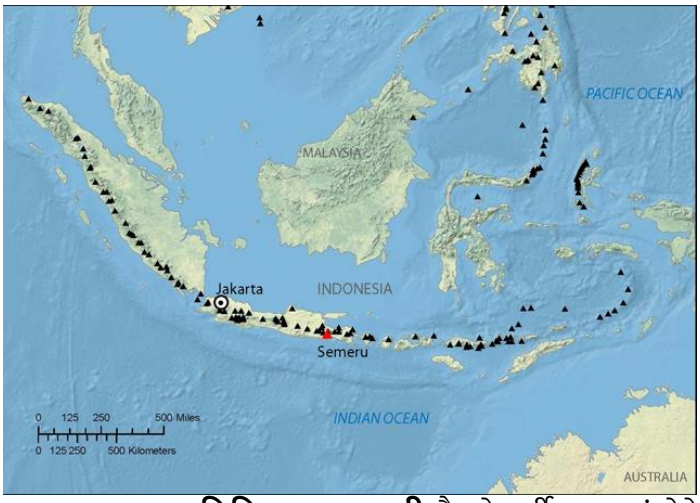

- यह एक **मिश्रित ज्वालामुखी** है जो पूर्वी जावा, इंडोनेशिया में स्थित है जिसमें महामेरू शिखर पर एक सक्रिय **जोनग्गरिंग सेलोको द्वार** है।
- यह सबडक्शन क्षेत्र में स्थित है, जहां **हिंद-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियाई प्लेट** के अंदर दबती है।
- यह जावा द्वीप पर सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसे **महामेरू** भी कहा जाता है, जिसका अर्थ संस्कृत में **"महान पर्वत"** होता है।

संबंधित सूचना

प्रशांत अग्नि वलय के बारे में जानकारी

- अग्नि वलय को परिवेष्टक प्रशांत पट्टिका भी कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर के साथ वह एक पथ है जहां की विशेषता सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार भूकंपों का आना है।
- इन स्थानों पर पृथ्वी के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
- यहां पर कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमाएं स्थित हैं जिसमें प्रशांत, जुआन डि फुका, कोकोज़, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, नाज्का, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपींस की प्लेटें शामिल हैं।
- अग्नि वलय के साथ ज्वालामुखियों और भूकंपों की बहुतायत का कारण क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति की मात्रा है।
- इससे प्रभावित देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया औऱ न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, और अन्य द्वीपीय देश जैसे कि सोलोमन द्वीप, फिजी, और मेलानेसिया, माइक्रोनेसिया और पॉलीनेसिया के कई देश शामिल हैं।

संबंधित शब्द

शीतलन वलय

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- प्रशांत प्लेट, जो अग्नि वलय में अधिकांश टेक्टोनिक गतिविधि को संचालित करती है, ठंडी हो रही है।
- वैज्ञानिकों ने खोजा है कि प्रशांत प्लेट का सबसे युवा हिस्सा (लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराना) ठंडा हो रहा है और प्लेट के पुराने हिस्से (लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना) की अपेक्षा तेजी से संकुचित हो रहा है।
- प्लेट के युवा हिस्से इसके उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते हैं- यह अग्नि वलय का सबसे ज्यादा सक्रिय हिस्सा है।

पेंसीलुंग्पा हिमनद

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- वाडिया हिमालियाई भूगर्भ संस्थान (WIHG) के अनुसार, लद्दाख की जांसकर घाटी में स्थित पेंसी लुंग्पा हिमनद (PG) घट रहा है।

यह अध्ययन चार वर्षों (2016-2019) के क्षेत्र पर्यवेक्षणों पर आधारित है।

प्रमुख परिणाम

- पेंसीलुंग्पा हिमनद जाड़ों के दौरान तापमान की वृद्धि और वर्षण में कमी की वजह से घट रहा है।

पतन की दर

- अध्ययन यह भी कहता है कि चार वर्षों के लिए क्षेत्र पर्यवेक्षणों (2015-2019) ने दर्शाया है कि हिमनद 6.7 प्लस/मी. प्रतिवर्ष की औसत दर से घट रहा है।

मलबे का आवरण

- यह अध्ययन यह भी इंगित करता है कि विशेष रूप से गर्मियों में हिमनद के घटाव और द्रवमान अधिशेष पर मलबे के आवरण का काफी प्रभाव होता है।

छोटा संग्रहण क्षेत्र अनुपात

- तीन वर्षों (2016-2019) के लिए द्रव्यमान अधिशेष आंकड़े एक नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं जिसमें छोटा संग्रहण क्षेत्र अनुपात है।
- अध्ययन यह भी सुझाव देता है कि वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप वायु तापमान में सतत वृद्धि की वजह से, बर्फ का गलना बढ़ जाएगा, गर्मियों के काल का वर्षण ऊंचाईयों पर बर्फ से वर्षा में बदल सकता है, और गर्मी और ठंडक के क्रम को प्रभावित कर सकता है।

पेंसीलुंग्पा हिमनद के बारे में जानकारी

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

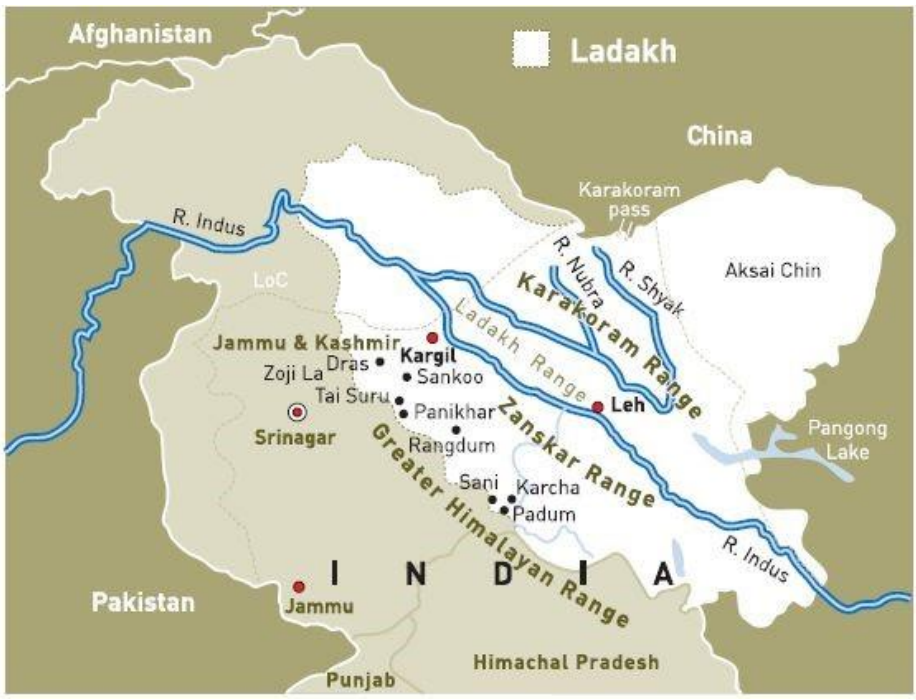

- यह जांसकर श्रृंखला, लद्दाख में स्थित है।
- जांसकर श्रृंखला लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है जो जांसकर को लद्दाख से अलग करती है।
- भूगर्भीय रूप से, जांसकर श्रृंखला टेथीज़ हिमालय का हिस्सा है।

पुतिन, मोदी के साथ UNSC बहस में शामिल होंगे

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन समुद्री सुरक्षा पर खुली बहस में शामिल होंगे जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता करेंगे। भारत एक महीने के लिए इस संस्था का अध्यक्ष है।

खबरों में और भी है

- यह आठवीं बार है कि भारत ने सर्वोच्च UN निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है।
- फिर भी सभी कार्यकालों में, यह 1950-51 में पहली बार यह चिरस्थायी सीख मिली कि कैसे अध्यक्ष पद के स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मामले कितने कठिन हो सकते हैं।

कश्मीर का मामला

- यह 1950-51 में था कि सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मसले ने गंभीर मोड़ ले लिया जिसने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को आश्चर्य में डाल दिया।
- भारत उस समय स्वतंत्रता के आरंभिक चरण से संघर्ष कर रहा था और 1947-48 के युद्ध के साथ ही तुरंत कश्मीर मामला उठ गया।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- यह मामला UN में 1 जनवरी, 1948 को उस समय उठा जब भारत ने UNSC से उस युद्ध पर चर्चा करने का अनुरोध किया जो पाकिस्तान से जनजातीय अनियमित लड़ाकों के आक्रमण के साथ शुरू हुआ था।
- भारतीय प्रस्तुतीकरण से "जम्मू एवं कश्मीर प्रश्न" का जन्म हुआ।
- **विवाद का शीर्षक 22 जनवरी, 1948 को परिवर्तित होकर "भारत-पाकिस्तान प्रश्न" हो गया।**
- 1948 से 1951 का काल काफी गर्म रहा जहां तक कश्मीर मामले का संबंध है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से लोच का प्रदर्शन काफी कम था। इस दौरन प्रथम UN प्रतिनिधि ओवेन डिक्सन के द्वारा स्थिति को सुलझाने के प्रयास असफल रहे।
- ऐसे परिदृश्य में, 30 मार्च, 1951 को, UNSC ने कश्मीर पर एक एंग्लो-अमेरिकी प्रस्ताव को लिया और सततता की एक प्रक्रिया को रखा जिससे UNSC में कश्मीर मुद्दे को लंबी जिंदगी मिल सके जिसे आखिरी बार बातचीत के लिए 1971 में लिया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 की समाप्ति के परिदृश्य में चीन द्वारा इस मुद्दे पर अगस्त 2019 में चर्चा की गई।

प्रस्ताव 91

- प्रस्ताव 91 ने भारत औऱ पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP) को UNMOGIP (भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह) द्वारा विस्थापित करने का निर्णय लिया।
- इसने **सर ओवेन डिक्सन की भूमिका** की तरह ही भारत और पाकिस्तान के लिए UN प्रतिनिधि की नियुक्ति का निर्णय लिया।
- **दूसरे निर्णय ने UN में लगभग कश्मीर मामले को संस्थागत कर दिया।**

'PM-दक्ष' पोर्टल और 'PM दक्ष' मोबाइल ऐप

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने 'PM-दक्ष' पोर्टल और 'PM-दक्ष' मोबाइल ऐप की शुरुआत की।

PM-दक्ष पोर्टल के बारे में जानकारी

- यह एक पोर्टल है जो एक ही जगह पर कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित सभी सूचना को उपलब्ध कराता है।

इस पोर्टल की कुछ विशेषताएं निम्न हैं:

- अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए एक जगह कौशल विकास से संबंधित सभी सूचना की उपलब्धता।
- प्रशिक्षण संस्थान के लिए पंजीकरण और उनकी रुचि के कार्यक्रम की सुविधा।
- व्यक्तिगत सूचना से संबंधित वांछित दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा।
- प्रशिक्षण काल के दौरान चेहरे और आंखों की स्कैनिंग के द्वारा प्रशिक्षुओं की उपस्थिति के पंजीकरण की सुविधा।
- प्रशिक्षण इत्यादि के दौरान फोटो और वीडियो क्लिप के साथ निगरानी सुविधा।

संबंधित सूचना

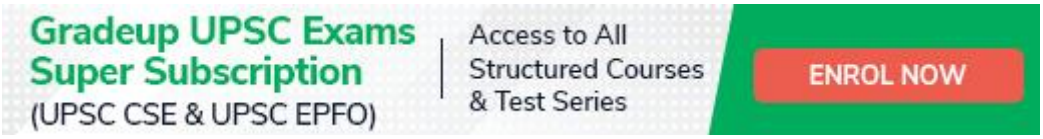

प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (PM-DAKSH) योजना के बारे में जानकारी

- इसका क्रियान्वयन 2020-21 वर्ष से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के अंतर्गत, पात्र लक्षित समूहों को निम्न पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं-
    (i) नया कौशल सीखाना/पुनः कौशल सीखाना
    (ii) लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम
    (iii) दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम
    (iv) उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP).
- इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्र कौशल परिषदों के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिनका गठन कौशल विकास और उद्यमिता एवं अन्य विश्वसनीय संस्थानों द्वारा किया गया है।
- कार्यक्रम का जोर अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले कौशलों को प्रदान करना है जिससे प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप नौकरियां मिलें अथवा स्वरोजगार उद्यम शुरू हों।
- यह कार्यक्रम सफाई कर्मचारियों को भी कुशल बनाता है जिसमें कचरा बिनने वाले, और महिलाएं शामिल हैं जिससे वे स्व-रोजगार गतिविधियों में शामिल हो सकें।
- इसका क्रियान्वयन तीन निगमों के द्वारा किया जाएगा:
    a. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC);
    b. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC); और
    c. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)

सरकार द्वारा प्रमुख प्रशासनिक सुधार

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्री ने कहा कि सरकार समय-समय पर प्रशासनिक सुधारों को करती है, जिससे ज्यादा क्षमता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जवाबदेही और मनमानेपन के दायरे को घटाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
- प्रशासनिक सुधारों का लक्ष्य ज्यादा क्षमता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जवाबदेही और मनमानेपन के दायरे को घटाने को प्रोत्साहित करना है।

कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

मिशन कर्मयोगी

- "मिशन कर्मयोगी" की शुरुआत करने से- जो लोक सेवाओं की क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCSCB) है, लोक सेवा के लिए एक नए राष्ट्रीय आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई है।
- यह क्षमतावान लोक सेवा डिलीवरी के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण उपकरण का एक समग्र सुधार है।

ई-समीक्षा

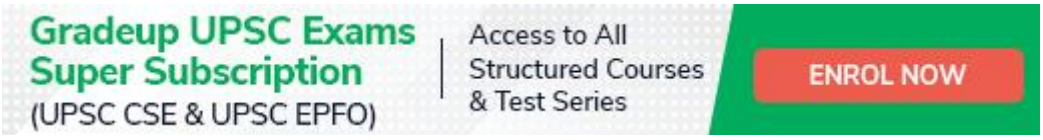

- यह महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में सर्वोच्च स्तर पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर निगरानी और तद्नुसार की गई कार्रवाई के लिए एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली है।

ई-ऑफिस

- ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना (MMP) को मंत्रालयों/विभागों को सक्षम बनाने के लिए मजबूत किया जा रहा है जिससे कागजविहीन कार्यालयों और सक्षम निर्णय लेने की ओर बढ़ा जा सके;

नियुक्तियों के लिए दस्तावेजों का स्व-प्रमाणन

- जून 2016 से, भर्ती करने वाली एजेंसियां अस्थाई नियुक्ति पत्रों को जारी कर रही हैं जो अभ्यर्थियों द्वारा स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को सौंपने पर आधारित है;

कनिष्ठ स्तर के पदों की भर्ती में साक्षात्कार को समाप्त करना

- जनवरी 2016 से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी समूह 'ग', समूह 'ब' (गैर राजपत्रित पदों) और समतुल्य पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है जिससे बेईमानी को रोका जा सके और चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता आ सके।

वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति

- संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों के नामांकन के लिए बहुस्रोत फीडबैक को लागू किया गया है;

बेहतर शासन सूचकांक 2019

- इसका शुरुआत की गई थी जो शासन की स्थिति का आकलन करता है, साथ ही राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्रों (UTs) द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का भी आकलन करता है।
- GGI का उद्देश्य मात्रात्मक आंकड़ों को उपलब्ध कराना है जिससे सभी राज्यो और केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा शासन की स्थिति की तुलना की जा सके। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को सक्षम बनाया जा सके कि वे शासन में सुधार और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोणों और प्रशासन की ओर झुकाव के लिए उपयुक्त रणनीतियों को बनाकर क्रियान्वित करें।;

ई-शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- यह सरकार को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है जिससे वह ई-शासन पहलों से संबंधित अनुभवों के विनिमय के लिए उद्योग और अकादमिक संस्थानों से विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत कर सकें;

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)

- सबसे ज्यादा शिकायत हासिल करने वाले मंत्रालयों/विभागों में सरकार CPGRAMS सुधार कर रही है। इसके लिए प्रश्नोत्तरी निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा रहा है, साथ ही क्षेत्र स्तर के कार्यकारियों को शिकायतों का स्वतः प्रेषण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे निपटारे का समय घटाया जा सके;

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

भारत, श्रीलंका और मालदीव सुरक्षा पर सहयोग करेंगे

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- भारत, श्रीलंका और मालदीव ने तीन देशों के सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारियों की हाल की वर्चुअल बैठक में सुरक्षा सहयोग के "चार स्तम्भों" पर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है।

वे निम्न क्षेत्रों को शामिल करते हैं-

a. समुद्री सुरक्षा,
b. मानव तस्करी,
c. आतंकवाद निरोध,
d. साइबर सुरक्षा,

संबंधित सूचना

कोलंबो सुरक्षा संगोष्ठी

- कोलंबो सुरक्षा संगोष्ठी तीन पड़ोसी देशों के बीच में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और प्रोत्साहित करेगी।
- इसकी पहल राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा 2011 में की गई थी जब वे रक्षा मंत्रालय में सचिव थे।
- यह पहल जो सैन्य और सुरक्षा सहयोग में समाहित है, क्षेत्र में इस मायने में महत्वपूर्ण है कि भारत, श्रीलंका और मालदीव के साथ वर्तमान भूरणनीतिक गतिकी को साझा करता है।
- इस वर्ष पूर्व में, भारत ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के एक द्वीप के पास चीन को दी गई विकास परियोजनाओं पर अपनी सुरक्षा चिंता व्यक्त की थी, जो भारत के दक्षिणी सीमा के पास है।

क्वाड के साथ बातचीत

- मालदीव की भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया समूह जिसे क्वाड कहते हैं, के सदस्यों के साथ बातचीत, पिछले वर्ष से बढ़ रही है, विशेष रूप से रक्षा सहयोग के क्षेत्र में।

ज़ायद तलवार 2021

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा, स्रोत-AIR)

खबरों में क्यों है?

- भारतीय नौसेना ने हाल में अबू धाबी के तट के पास UAE की नौसेना के साथ 'ज़ायद तलवार 2021' द्विपक्षीय अभ्यास किया।

ज़ायद तलवार 2021 के बारे में जानकारी

- यह एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और UAE की नौसेनाओं के बीच में होता है।

उद्देश्य

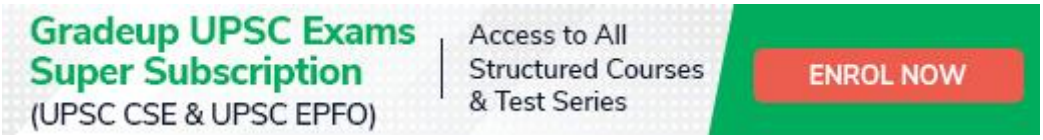

- ज़ायद तलवार 2021 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दो नौसेनाओं के बीच में अंतरसंक्रियता और सहक्रिया को उन्नत करना है।

नोट:

- **UAE के साथ, भारत का इन-UAE बिलत (द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास) साथ ही डेजर्ट ईगल-II (द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास) होता है।**

इन लाइन परमिट

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- लद्दाख प्रशासन ने हाल में केंद्र शासित क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत को समाप्त कर दिया है।
- अधिसूचना के अनुसार, भारतीय नागरिकों के लिए जिसमें घरेलू पर्यटक और नागरिक भी शामिल हैं, के लिए अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।

इनर लाइन परमिट के बारे में जानकारी

पृष्ठभूमि

- इनर लाइन परमिट बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन कानून 1873 का विस्तार है।
- ब्रिटिश ने यह कानून बनाया था जिसमें कुछ नामांकित क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- ऐसा साम्राज्य के हितों को कुछ राज्यों में ब्रिटिश प्रजा (भारतीय) को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोक संरक्षित किया गया था।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

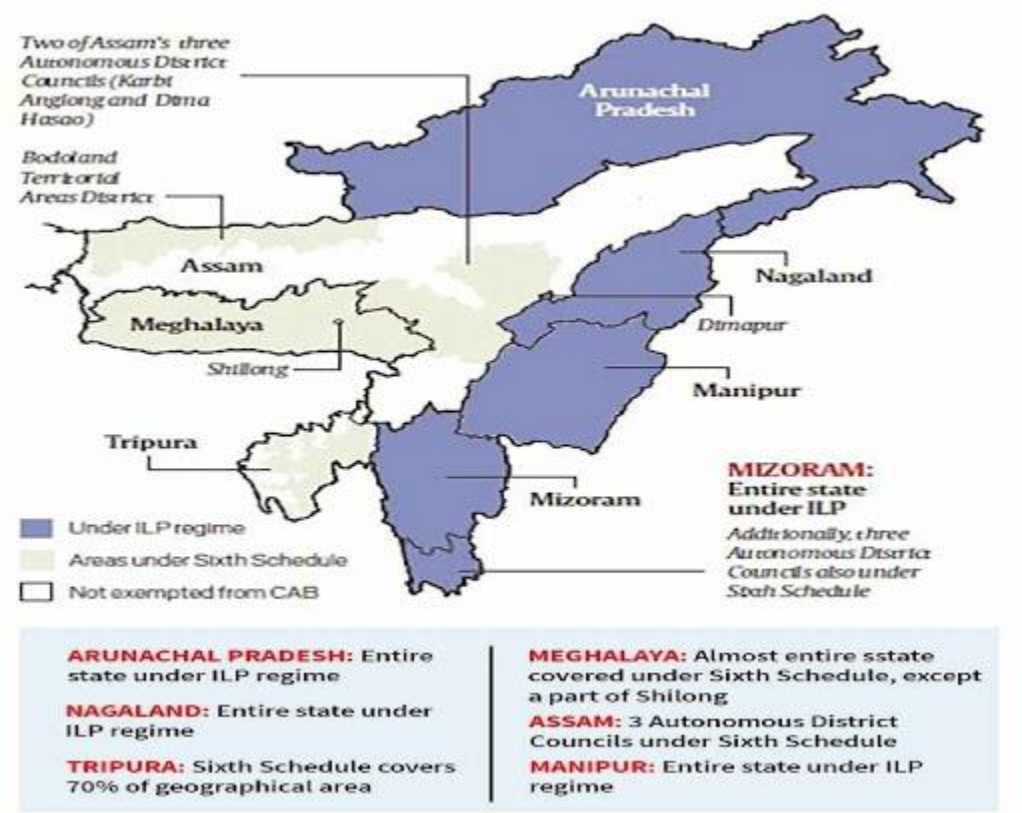

इनर लाइन परमिट के बारे में जानकारी

- यह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिससे सीमित समय के लिए संरक्षित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को यात्रा की अनुमति दी जा सके।
- कुछ बाहरी राज्यों से आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इस तरह के परमिट को हासिल करने की प्रतिबद्धता है।
- वर्तमान में, **चार उत्तर-पूर्व के राज्य इसमें शामिल हैं, जिनके नाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम हैं। ये राज्य इनर लाइन से संरक्षित हैं, औऱ हाल में मणिपुर को भी इसमें शामिल किया गया।**
- रहने की अवधि और किसी गैर निवासी द्वारा यात्रा के लिए अनुमति वाले क्षेत्र दोनों का निर्धारण इनर लाइन परमिट के द्वारा होता है।
- **ILP को संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।**

चीन पर वैश्विक औसत से ज्यादा तापमान वृद्धि का असर: सरकार की ब्लू बुक

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- चीन 2021 में मौसम परिवर्तन पर एक ब्लू बुक जिसे चीन मौसम विज्ञान प्रशासन **(CMA)** ने इस सप्ताह प्रकाशित किया है, में आगाह किया गया है कि 1961 से 2020 के मध्य चरम भारी वर्षण में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, और मध्य 1990 के दशक से देश में चरम गर्मी की घटनाएं काफी बढ़ गईं हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- ब्लू बुक के अनुसार, चीन एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसपर वैश्विक मौसम परिवर्तन का काफी प्रभाव है। यहां समान अवधि के दौरान वैश्विक औसत की अपेक्षा तापमान में वृद्धि काफी ज्यादा है।
- स्टेट मीडिया के अनुसार, 2020 में, **चीन के तटीय क्षेत्रों में समुद्री स्तर 1993 से 2011 के बीच के औसत से 73 मिमी. ज्यादा था, यह 1980 से तीसरी सबसे बड़ी वृद्धि है।**
- गर्मियों में समुद्री तापमान की लगातार वृद्धि की वजह से **विवादास्पद दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों में गंभीर प्रवाल विरंजन की स्थिति उत्पन्न हुई है।**
- ब्लू बुक ध्यान दिलाती है चीन का मौसम जोखिम **सूचकांक 1961 से 2020 के बीच में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है, और 2020 में यह संख्या 10.8 थी, उस काल की यह तीसरा सबसे ऊंचा मान है।**
- ब्लू बुक चीन और वैश्विक तौर पर मौसम परिवर्तन पर नवीनतम निगरानी सूचना उपलब्ध कराती है, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, हिममंडल, स्थलीय बायोमंडल और मौसम परिवर्तन के संचालक कारकों पर आंकड़े शामिल हैं।

ICMR का कहना है कोविशील्ड-कोवैक्सीन का मिश्रण बेहतर संरक्षण देता है

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने हाल में अपने निष्कर्षों को जारी किया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि एक एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफार्म आधारित टीका संयोजन के साथ टीकाकरण जिसके बाद एक निष्क्रिय संपूर्ण वायरस टीका हो, न केवल सुरक्षित है बल्कि बेहतर प्रतिरक्षाजनकता भी हासिल करती है।
- भारत में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम दो टीकों के साथ शुरू हुआ था-एस्ट्राजेनेका की ChAdOxI-nCov-19 (भारत में कोविशील्ड नाम) और निष्क्रिय संपूर्ण विरियॉन BBV152 (कोवैक्सीन)।

एक अनुकूल प्राइम बूस्ट दृष्टिकोण का पालन किया गया।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

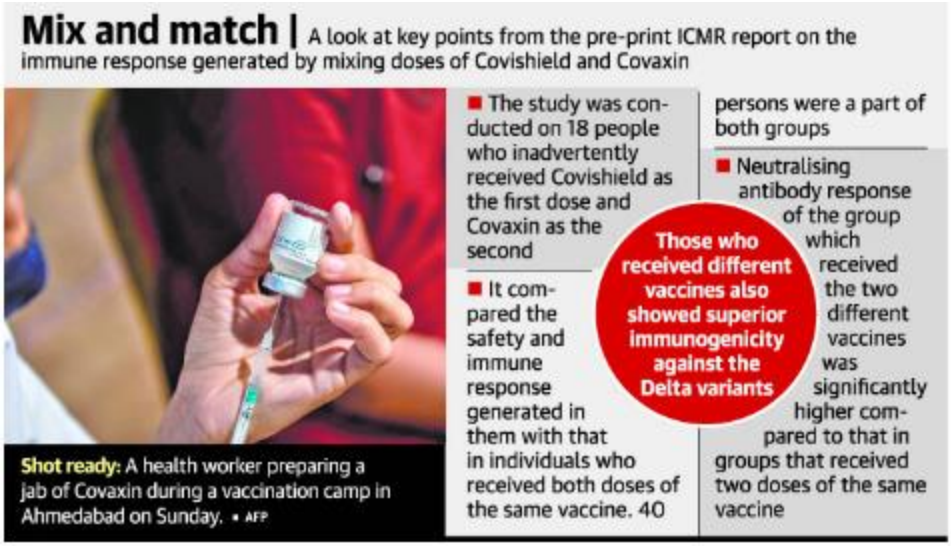

मुद्रण पूर्व रिपोर्ट

- लेकिन, उत्तर प्रदेश में 18 व्यक्तियों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, अनजाने में पहला टीका कोविशील्ड का और दूसरा टीका कोवैक्सीन का लगवाया था।
- **अपने अध्ययन में** ICMR **ने इन व्यक्तियों की सुरक्षा और प्रतिरक्षाजनकता की तुलना उन व्यक्तियों के साथ की जिन्हें केवल एक ही प्रकार का टीका लगा था- कोविशील्ड या कोवैक्सीन।**
- पूर्व मुद्रण रिपोर्ट जिसका शीर्षक "सेरेंडीपिटस कोविड-19 वैक्सीन-मिक्स इन उत्तर प्रदेश, इंडियाः सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनेसिटी एसेसमेंट ऑफ ए हेट्रोलॉगस रिजीम" है, को सहकर्मी समीक्षा के द्वारा प्रमाणीकृत नहीं किया गया था और इसका प्रयोग क्लीनिकल प्रयोग को निर्देशित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

नोट:

- पूर्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकों के मिश्रण के खिलाफ चेतावनी दी थी, उसका कहना था कि टीकों के मिश्रण और सुमेलन पर काफी कम सूचना उपलब्ध है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW